लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 25, शनिवार, 9 जुलाई, 1977/18 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 25, Saturday, July 9, 1977/Asadha 18, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGEL
समितियों के लिये निर्वाचन :	Elections to Committees :—	1-4
(एक) प्राक्कलन समिति	(i) Committee on Estimates . .	1
(दो) लोक लेखा समिति	(ii) Committee on Public Accounts; .	1-2
(तीन) सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति	(iii) Committee on Public Undertakings .	2-3
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	(iv) Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	3-4
अनुदानों की मांगें—1977-78—	Demands for Grants—1977-78—	4
उद्योग मंत्रालय	Ministry of Industry . . .	
श्री सुशील कुमार धारा	Shri Sushil Kumar Dhara . . .	4
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder .	4-5
डा० बापू कालदते	Dr. Bapu Kaldaty .	5-6
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua. . . .	6-8
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narayan Nayak .	8-9
फादर एन्थनि मुरमु	Father Anthony Murmu . .	9
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M.N. Govindan Nair . . .	9-10
डा० आर० रोथुआम	Dr. R. Rothuama . . .	10-11
श्री राम सागर	Shri Ram Sagar.	11
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C. N. Vishwanathan . .	11-13
श्रीमती वी० जयालक्ष्मी	Shrimati V. Jayalakshmi . . .	13-14
श्री एन्थू साहू	Shri Ainthu Sahoo	14-16
श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J. Rameshwara Rao . .	16-17
श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा	Shri Chandradeo Prasad Verma . .	17
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	17-18

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री विनोद भाई बी० शेठ	Shri Vinodbhai B. Sheth . . .	18–20
श्री सुभाष आहुजा	Shri Subhash Ahuja . . .	20
श्री के० मालन्ना	Shri K. Mallanna	20–21
श्री लक्ष्मण राव मानकर	Shri Laxman Rao Mankar . .	21
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	21–22
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh . .	22
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai; . .	23
श्री बशीर अहमद	Shri Bashir Ahmad . . .	23–24
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	24–25
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri G. Narsimha Reddy . . .	25–26
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand . . .	26
श्री पूर्ण सिन्हा	Shri Purna Sinha	26-27
श्री दिनेश चन्द्र जोरदर	Shri Dinesh Chandra Joarder . .	27-28
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri Rajagopal Naidu . . .	28

लोक सभा

LOK SABHA

शनिवार, 9 जुलाई, 1977/18 आषाढ़, 1899 (शक)

Saturday, July 9, 1977/Asadha 18, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

समितियों के लिये चुनाव
ELECTIONS TO COMMITTEES

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1978

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें, 1977-78

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78

उद्योग मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा उद्योग मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेगी। कुछ माननीय सदस्य इस चर्चा का समय बढ़ाना चाहते हैं। सभा का इस बारे में क्या विचार है।

श्री श्रीकान्तम नायर : यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि श्रम मंत्रालय की मांगों पर सोमवार को चर्चा की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः इन मांगों पर चर्चा आज ही समाप्त की जाये। मंत्री महोदय 5 बजे शाम् उत्तर देना शुरू कर सकते हैं।

Shri Sushil Kumar Dhara (Tamluk) : Yesterday, the hon. Minister said that steps will be take to curb monopoly. In addition to that it is also necessary to implement the report of the Monopolies Commission.

It is necessary to provide bank assistance for developing rural areas and small industries. In our area, fruits are grown on a large scale. If bank assistance is made available, unemployed youngmen can set up small fruit processing units. The hon. Minister should see that necessary finance and implements are made available to these youngmen at one place so that they have not to run from one place to another.

Haldia port was constructed about 20 years ago but the industrial complex has not so far came up there. It is time when attention can be paid towards this matter. Some agro-industries should also be developed there. We should set up the small industries on the Japanese pattern wherein mother industry and ancillary industries are set up side by side.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय को औद्योगिक नीति के बारे में दिए गए वक्तव्य के लिए बधायी देता हूं। मंत्रालय के प्रतिवेदन में उद्योगों में व्याप्त स्थिति का एकतरफा चित्र खींचा गया है। वास्तव में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है और इसलिए आगे आने वाले समय में भी उद्योगों में मंदी की सम्भावना है।

कई औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है और सरकार ने यह बात जनता के सामने स्वीकार नहीं की कि अर्थव्यवस्था के भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस संकट से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं । ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है । कृषि पदार्थों की कमी के कारण गरीब किसान तबाह हो गया है और वह अपने उत्पादों को बहुत कम कीमत पर बेचने को विवश हो गया है ।

कई उद्योग अपनी क्षमता का केवल 30 से 40 प्रतिशत तक ही उपयोग कर रहे हैं । यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रयुक्त क्षमता के कारण औद्योगिक उत्पादन को 600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की हानि हो रही है । सरकार यह सुनिश्चित करने में असफल रही है कि अप्रयुक्त क्षमता अल्पतम समय में प्रयुक्त की जा सके ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अच्छे प्रवन्ध और सुधार पर अधिक बल दिया जाना चाहिये तभी सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र की तुलना में बेहतर हो सकेगा । कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च अधिकारी उपक्रम को तबाह करने पर तुले हुए हैं । हमें उन अधिकारियों का पता लगाना है तथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी है । दुर्गापुर में भ्रष्ट प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। लेखापरीक्षण आपत्तियों के बावजूद भी कदाचार जारी है। इन कदाचारों की जांच एक जांच आयोग के गठन द्वारा की जानी चाहिये ।

पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु कलकत्ता पत्तन की परिवहन क्षमता में सुधार किया जाना चाहिये और जिन महीनों में पानी की कमी होती है, उनके दौरान फरक्का के जरिए गंगा से 40,000 क्यूसेक जल प्राप्त करने की अनुमति दी जाये। उद्योग मंत्री को राष्ट्रहित में इस समस्या के शीघ्र समाधान हेतू सम्बद्ध मंत्रालय से इस बारे में बातचीत करनी चाहिये।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास के लिए सरकार को हाल्दिया में जहाज निर्माण के लिए दिए गए प्रस्ताव का कार्यान्वियन करना चाहिये और हाल्दिया पैट्रो रसायन परियोजना का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाये ।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है, इसे हल करने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों को उचित संरक्षण दिया जाये तथा आवश्यक पुंजी देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाये ।

सदन को आश्वासन दिया जाना चाहिये कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सब कुछ किया जाएगा । बंगाल के तीन पिछड़े जिलों और विशेषकर पुरनिया जिले की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

Dr. Bapu Kaldaty (Aurangabad) : I am happy to see that the Minister has enumerated the Government policy io regard to industry.

It is hoped that the industrial policy that Janta party is adopting will help us in solving the country's problem. Our economy is an underdeveloped economy. For converting an underdeveloped economy into developed economy it is necessary that national production

increases at least at the rate of 11 per cent per year. But we have hardly achieved 5 per cent which is very unsatisfactory. When we started planning it was stated that by 1980 i.e. by the end of Fifth Plan we will reach the take off position. But we are lagging far behind. If we want to reach the take off stage the rate of production will have to be stepped up.

If you look at the district-wise figures of industrial units it will be seen that all industrial development has concentrated in the urban areas particularly in the metropolitan cities. In Maharashtra for example, in 1971, 54 per cent of the registered units were in Bombay and Thana alone. On the other hand in the backward region of Marathwada only 4 units were registered. This shows that the previous Government had paid little attention to the backward areas. Same attitude has been adopted in case of U.P. also. It is time some concrete steps are taken for the dispersal and decentralisation of industries. The Government has paid very little attention to the agro based industries. The growth rate of agro based industry as compared to Metal and Chemical industries is very less. On this account regiona imbalances have grown.

It is also necessary that more attention is paid to opening of labour intensive industries. So far we have been setting up more and more capital intensive units and it is this which is responsible for the growth of unemployment in the country. But setting up of labour industries should not mean setting up of industries with old technology. We should develop a new technology which not only brings about dispersal of industries and modernises them but also rid the society of exploitation.

It is regrettable that while nothing is being done to develop industries in Marathwada, for Maharashtra the Twin Bombay Project is being prepared which will cost Rs. 400 crores while we admit the need of this project there is need to decide priorities in spending money. Neglect of backward areas give rise to law and order problem. This should not happen.

So far as Khadi and village Industries Board is concerned it has become an institution of political patronage and corruption is rampant therein. There is need to make a thorough inquiry in this regard.

In the past several Committees like Wanchoo Committee, Pandey Committee, Dutt Committee, etc., had been appointed to make recommendations for the setting up of small industries. But no attention has ever been paid to implement those recommendations. There is great need to provide credit and marketing facilities to these industries.

It is not under stood why the big companies are allowed to manufacture articles like soap, powder, match box etc., which can be produced by small industries. At present the small industries produce 4,000 items but so far only 250 items have been reserved for them. We should clearly specify the items which can be produced by the small units and the big units should not be allowed to produce those items. This is the only pay to develop the small Industries.

It is very necessary to take the public sector industries to the backward areas. It is also necessary that preference is given to the local people in the matter of employment.

Big units should also not become islands of plenty in the sea of poverty but must serve inducing effect for more industries and more employment.

At present there are a number of corporations. These corporations have also become an instrument of patronage. Their number should be reduced and government should think about setting up an autonomous composite Corporations.

With these words I conclude.

श्री वेदव्रत वरुआ (कालियाबोर) : मंत्री महोदय के नए विचारों का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वह अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे ।

जनता पार्टी के सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस ने औद्योगिक विकास के लिए सही दिशा में कार्य नहीं किया है परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत को औद्योगिक आधार दिया भारत में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है । स्वतन्त्रता के समय भारत में गिने चुने कपड़े के कारखाने थे इस समय हमारे यहां विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जिनकी बराबरी चीन भी नहीं कर सकता । निःसन्देह कुछ कमियां रह गई हैं । लेकिन अर्थव्यवस्था के विकास के समय ऐसी कमियां रहती ही हैं । सरकार का काम इन कमियों को

दूर करना तथा अर्थव्यवस्था का विकास स्वस्थ आधार पर करना है । मंत्री महोदय तथा अन्य अनेक सदस्यों ने लघु उद्योगों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है परन्तु तत्सम्बन्धी नीति अभी अस्पष्ट है । इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि लघु उद्योगों का बड़े उद्योगों, बहुराष्ट्रीय उद्योगों विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने और अन्य बातों के साथ क्या सम्बन्ध है । इन बातों पर सरकार ने कभी भी विचार नहीं किया ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि बड़े ब्यापार गृहों की बड़ी कम्पनियों में 50 प्रतिशत शेयर पूंजी भी नहीं हैं। उनके इस स्पष्ट कथन की मैं सराहना करता हूं । टाटा बन्धुओं का टेलको और अन्य कम्पनियों में मुश्किल से 3 प्रतिशत का शेयर है बिरला बन्धुओं के हिन्दुस्तान मोटरज और प्रीमियर आटोमोबाइल्स के केवल 15 प्रतिशत शेयर है । अतः यह सोचना कि अधिक शेयर होने के कारण वह कम्पनियों पर नियंत्रण कर रहे हैं ठीक नहीं है । वह काम खुद न चला कर उन लोगों से चलवाते हैं जो अपने काम में पूर्णतः दक्ष हैं ।

मैं तकनीकी जानकारी की स्थिति जानना चाहता हूं । हमने भी विदेशी जानकारी का आयात किया । आज विश्व में सभी देशों को तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है । बिना जानकारी के देश का औद्योगिकीकरण नहीं हो सकता । हमें भी एक ऐसी जानकारी की आवश्यकता है जो हमारे देश की स्थिति के अनुरूप हो । हमारी जनशक्ति अपार है । इस समय हमारे उद्योग विदेशी सहयोग से चल रहे हैं । इस प्रकार देश में विदेशी जानकारी का आयात किया गया है । एक कम्पनी विदेशी सहयोग से कड़े उद्योग स्थापित करती है । तथा उससे प्राप्त जानकारी को गुप्त रखा जाता है । इस सम्बन्ध में यह समझौता होता है कि यह जानकारी किसी और को नहीं दी जाएगी परन्तु बार बार वही जानकारी दूसरी कम्पनियों को भी दी जाती हैं । पिछली सरकार ने इस प्रकार बार बार जानकारी के आयात पर रोक लगाने का प्रयत्न किया । अब इस पर पूरी तरह रोक लगाने का समय आ गया है । दस वर्ष पहले यह संभव नहा था क्योंकि उस समय हम इतने शक्तिशाली नहीं थे । परन्तु अब हम पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है और सरकार यह कह सकती है कि बार बार वही जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

कई लोगों का कहना है कि विदेशियों को भी साम्य शेयर दिए जायें अन्यथा वह उद्योग में रुचि नहीं लेंगे लेकिन एक बार अगर आप विदेशी कम्पनियों को स्वदेशी कम्पनियों की प्रतियोगिता में ला खड़ा करेंगे तो स्वदेशी कम्पनियों बिल्कुल तबाह हो जायेंगी । मैं इस सदर्भ में आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं विदेशी नामों के प्रति लगाव ही तबाही का बड़ा कारण है ।

बड़ी कम्पनियों लघु उद्योगपतियों से सस्ते दाम पर माल खरीदकर आगे महंगा बेच देती हैं ।

बहुराष्ट्रीय फर्मों के बारे में मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये क्योंकि यदि हम लघु उद्योगों को मदद देना चाहते हैं तो हम इस बहुराष्ट्रीय फर्मों को लघु उद्योगों से प्रतियोगिता नहीं करने दे सकते ।

भारत सरकार ने बजट में एक नीति सम्बन्धी निर्णय का उल्लेख किया है कि देश में निर्मित मशीनें मिलने पर भी पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाएगी। यह बहुत घातक और

[श्री वेदव्रत बरुआ]

गलत नीति है। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या सरकार सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देने वाले औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प से और 1972 की लाइसेंस नीति से बंधी है अथवा नहीं। यह बहुत विकसित नीति तो नहीं है परन्तु बड़े उद्योग गृहों पर रोक लगाने के लिए यह एक काम चलाऊ नीति तो है ही।

अब समय आ गया है कि औद्योगिक नीति को लघु उद्योग प्रधान बनाया जाए। बीस साल पहले नेहरू औद्योगिक नीति को यह स्वरूप नहीं दे सकते थे क्योंकि उस समय देश के लिए औद्योगिक आधार बनाना था। वह आधार बन गया है तथा कांग्रस ने पहला चरण पूरा कर दिया। जहां तक दूसरे चरण का संबंध है हमारे दल को रोज़गार के संबंध में व्याप्त अभावों को दूर करना चाहिए तथा ऐसे तकनीक का विकास करना चाहिए जो लघु उद्योगों के लिए उपयोगी हो।

गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता दी गई है। उन्हें पूंजी निवेश की सुविधाएं प्रदान की गई बहु राष्ट्रीय फर्मों को आयात की अनुमति दी गई है जिसमें घड़ियों का आयात भी शामिल है। बड़े व्यापार गृह छोटे एककों को रुग्ण बनाते हैं और आप उन्हें इतनी बड़ी बख्शीश दे रहे हैं। लघु पमाने के उद्योगों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। विद्युतकरघों को जो प्रोत्साहन दिये गये हैं उनसे हथकरघा उद्योग में लगे लोगों का अहित होगा। इससे लघु पैमाने के उद्योगों को काफी कठिनाइयां होंगी।

दो महीले पहले सरकार ने घोषणा की थी कि सरकारी क्षेत्र द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों को दिया जाने वाला 10 प्रतिशत का मूल्य लाभ समाप्त कर दिया जायेगा। सरकारी प्रतिष्ठानों को यह लाभ इसलिए दिया जाता था क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं दिया जा सकता था। अगर यह मूल्य लाभ देना बन्द कर दिया जाएगा तो कोई भी माल सरकारी क्षेत्र से नहीं खरीदेगा। डाक्टरों ने भी इण्डियन ड्रग्स फार्मेस्यूटिकल लिमिटेंड से शल्य चिकित्सा के कार्य में आने वाले उपकरणों को खरीदना बन्द कर दिया है।

आशा है मंत्री महोदय इन पहलुओं पर विचार करेंगे।

Shri Laxmi Narayan Nayak (Khajuraho) : It is repeatedly said that there is great need to set up industries in the rural areas. But when time for action comes what we find that all industries are set up in the citites. This trend will have to be checked. Let Government take a policy decision that henceforth all new industries will be set up in the rural areas and preference will be given to the backward areas. Land is available at cheaper rates in rural areas. Labour is also in abundance. Raw material is also easily available. Therefore I submit that all new industries should be set up in backward areas first. This is the only way in which we can remove poverty and bring about equality in our country.

As regards textiles, there is a general complaint that stocks are accumulating and that it is not being sold. It is so because the people do not have purchasing capacity. There is lot of disparity between mill owners and farmers. The rich are becoming richer day by day and the poor are becoming poorer day by day.

It has been said again and again that workers will be given due participation in management. But only this will not be enough. We should give that due share in the profit. Socialistic set up should be brought right earnstly.

It is also necessary that some items be specifically demarcated for production in the small scale industries. Concessions in excise duty etc. should also be given to these industries.

Bamboo is supplied at a very low price to the Oriental Paper Mill of Madhya Pradesh when the tribals have to pay much more. This should be looked into. While setting up this

mill it was provided in the agreement that the dirty water would be collected in a tank. But this tank was not constructed and the water is flowing into some river. This has created health hazard in that area. But no action is being taken against Birlas, who owned that mill. Government should look into the matter.

In Bastar area contract for cutting bamboos have been given to Shri Bangad. Government should go into the matter and ensure that there is no discrimination made in regard to the royality.

The schemes for the self employment of educated unemployed and engineers are only on papers. The loan applications of these persons should be considered sympathetically.

In the Bundelkhand area there are no industries. Government should see that some industries are set up there so that the local people can)get employment.

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृषि और उद्योग देश के जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि उद्योग मंत्रालय पर चर्चा का समय बढ़ाया जाए। मेरा विश्वास है किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे और सदन को इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु कठिनाई यह है कि श्रम मंत्री अपने मंत्रालय के सम्बन्ध में सोमवार तक उत्तर देना चाहते हैं क्योंकि फिर उन्हें गोदी कर्मचारियों से बात करने जाना है। अतः यदि सदन सोमवार को देर तक बैठने को राजी हो तो उद्योग मंत्री भी सोमवार को उत्तर दे सकते हैं।

Father Anthony Murmu : The Industrial policy as enunciated by Government in the budget documents indicates the measures to be taken for the development of backward regions. But this policy would be given all support only when it is found that the policy is being implemented in true spirit.

It is quite well that heavy industries have been started in the country. But there are some drawbacks in this regard. The industries have not been started keeping in view the requirements of local population. As a result, the industries opened in tribal areas became an instrument for exploitation of tribal people. The local tribals are not educated or trained and so they do not get employment there. The result is that tribals have now became beggers. Therefore, the local people should be given technical training and they should be absorbed in those industries.

Then, the local tribals have to face another difficulty in regard to police verification and caste certificate, before they are given an employment. The procedure for obtaining a caste certificate and the procedure of police verification should be simplified. At least 40 per cent of the local scheduled castes and scheduled tribes should be given employment. It is the obligation of the Government to pay particular attention to the welfare of people of backward communities.

Bihar is a very backward state and the Industries of that State should be made agriculture oriented. In the Santhal Pargana, which is a tribal district. a sugar)factory or paper mill or chemicals factory)can be opened there. The geological survey of the area has indicated that minerals such as bauxite and coal are available there. Therefore, Government should see that local people are provided employment in coal mines of factories. Local tribals have great potentialities which should be utilised, and they should be given all opportunities to join the mainstream of life in the country.

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का स्वागत है क्योंकि यह बजट में घोषित औद्योगिक नीति से हट कर है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सरकारी क्षेत्र को मजबूत किया जायेगा। और एकाधिकारियों पर अंकुश रखा जाएगा। बजट प्रस्तावों को लागू करने के लिए मंत्री महोदय द्वारा पेश की गई अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का हम हृदय से समर्थन करेंगे।

वित्त मंत्री ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि सरकारी क्षेत्र ठीक प्रकार काम कर रहा है। परन्तु यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के लिए आवंटन को 54 प्रतिशत से घटा कर 49 प्रतिशत कर दिया गया है। संगठित क्षेत्र की सर्वथा उपेक्षा की गई है।

रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए ग्रामोद्योगों को पूरा बल देना एक अच्छा कदम है इससे एक सीमा तक ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या हल होगी।

[श्री एम० एन० गोविन्दन नायर]

बीड़ी पर उत्पादन कर लगाने से इस उद्योग के लोगों को बड़ी कठिनाई हो गई है। लाखों लोग इस उद्योग पर आश्रित हैं। अतः मंत्री अपना प्रभाव डाल कर इस शुल्क को समाप्त करायें। कम से कम सहकारी संस्थाओं को इससे छूट दी जाए। मंत्री महोदय लघु और घरेलू उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं। परन्तु ये उद्योग ऋण और भारी दरों की कठिनाई का सामना कर रहे है। इन उद्योगों में लगे लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम दर पर ऋण दिया जाये। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

पिछले वर्ष उद्योगपतियों पर 4 प्रतिशत बोनस देने के लिए जोर डाला गया। इस संबंध में सरकार की क्या नीति है। सरकार इस ओर ध्यान दे और निश्चित नीति का निर्धारण करे जिससे कर्मचारियों को इस वर्ष उचित बोनस मिल सके। अन्यथा देश भर में श्रमिक समस्या उठ खड़ी होने का डर है।

डा० आर० रोथुआम (मिजोरम) : ग्रामीण क्षेत्र का समान विकास करने के लिए लघु उद्योगों पर जोर देने के लिए जनता सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु पहाड़ी क्षेत्र विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास की ओर कभी भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में मीजोरम एक बड़ा राज्य है जो आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है।

मिजोरम में इस समय कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मिजोरम में छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शिक्षा ले सकें। इसलिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना वहां की जाये।

राज्य में कोई भी उल्लेखनीय उद्योग नहीं है। वहां एकमात्र सरकारी फार्म है जो कि त्रिपुरा से लगी हुई पश्चिमी सीमा के निकट लोखि चेरा में स्थित है। मिजोरम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है तथा उसका अधिकांश क्षेत्र घने वनों से ढका हुआ है। वहां विभिन्न प्रकार की लकड़ियां तथा बांस होता है। वहां प्रचुर मात्रा में विद्यमान वन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के वन-आधारित उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। अतः प्लाइवुड फर्नीचर और टिम्बर आदि के कारखाने वहां लाभकारी ढंग से चलाये जा सकते हैं। यहां सर्वत्र सभी प्रकार के बांस बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। इनसे वहां कागज मिलों को बड़ी मात्रा में कच्चा माल भी उपलब्ध हो सकता है। मिज़ोरम में उपलब्ध बांस देश की सभी कागज मिलों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। किन्तु इन बांसों का उपयोग खेती के लिए किया जाता है।

मिज़ोरम में कई नदियां हैं जो कि उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही दिशाओं को बहती हैं। इनमें से कई नदियों पर कई स्थानों पर ऊंचे-ऊंचे जल प्रपात हैं। इन प्रपातों का उपयोग पन-बिजली का उत्पादन करने में किया जा सकता है। इस समय राज्य में बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के फल तथा सब्जियां होती हैं। अदरक तो यहां का मुख्य उत्पादन है। अतः इन वस्तुओं की बिक्री के लिए वहां उद्योग आरम्भ किया जा सकता है। जब श्री जगजीवन राम कृषि मंत्री थे तो एक बार वह मिजोरम गये थे। उन्हें वहां के प्राकृतिक साधनों के बारे में पूरा पता है।

हमारे राज्य के कई भागों में खनिज भंडार भरे पड़े हैं। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित कोलोडाइनों नदी के पानी में प्राकृतिक गैस की मात्रा बहुत अधिक है। सर्वेक्षण और उन्हें निकालने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई प्रयास न किये जाने के कारण ये सभी खनिज पदार्थ बिना निकाले वैसे ही पड़े हैं।

मिजोरम में संचार की गंभीर समस्या है, जिसके कारण मिजोरम एक तरह से समूचे देश से पृथक् सा है। यातायात सुविधाओं के अभाव में वहां के प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाना सम्भव नहीं है। इसका उसकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मिजोरम में कोई रेल लाइन तथा हवाई अड्डा नहीं है।

केरल के पश्चात् साक्षरता की प्रतिशतता में दूसरा स्थान मिजोरम का है। वहां के लोग शिक्षित और समझदार हैं। किन्तु चूंकि अन्य राज्यों की तुलना में वहां का आर्थिक स्तर नीचा है इसलिए वे लोग यह महसूस करते हैं कि केन्द्र सरकार ने हमेशा ही मिजोरम की उपेक्षा की है।

मुझे आशा है कि मिजोरम जैसे पिछड़े क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। हमें वहां के लोगों की आर्थिक दशा उनकी कठिनाइयों आदि को समझने का प्रयास करना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाये तभी हम वास्तविक समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। हमें देश के प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान रखना है तभी हम एक परिवार की तरह रह सकते हैं।

Shri Ram Sagar (Saidpur) : The real development of a nation depends on formulating a proper industrial policy. It helps in removing economic disparity and abridge the gap between rich and poor. At the same time it gives more and more opportunities for employment.

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए
Shri M. Satyanarain Rao *in the Chair*]

During the thirty years of Congress regime, there has been concentration of money and industrial power in a few hands. While a number of licences and permits were given to big business houses, smaller people or new entrepreneurs had not been given any assistance in setting up their industries. Government must see that now this process is reversed. The monopoly of a few big houses must be broken and more emphasis should be laid on setting up industries in rural areas.

It is wrong to say that the Janta Party is against large scale industries. We want Capital industries to be on the large scale sector, but the problem of unemployment can not be solved unless small scale industries are developed expeditiously.

Nationalized Banks have been asked to help the entrepreneurs by giving them loans etc. But the present rules are rigid. The rules for granting loans should be liberalised in favour of new entrepreneurs.

During 30 years of Congress rule,the benefit of planning and development did not percolate to the poorer sections of society, especially to Harijan and Adivasis.

Government must see that these persons are provided with necessary facilities for gainful employment.;

The Eastern part of Uttar Pradesh is one of the most backward regions in the country. 50 per cent of the people there are landless labour. There are no industries and big projects to provide emplyment to people. Immediate steps should be taken for the development of the region. The Report of Patel Committee in respect of development of that region must be implemented.

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरुपत्तूर) : प्रतिवेदन में बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी में कार्य होना आरम्भ हो गया है। ऐसी स्थिति में दक्षिणी क्षेत्र,

[श्री सी० एन० विश्वानाथन]

विशेषतया तमिलनाडु की क्या स्थिति होगी ? प्रधान मंत्री और उद्योग मंत्री के इन वक्तव्यों के संदर्भ में कि गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी नहीं थोपी जायेगी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि फिर गैर-हिन्दी भाषी लोगों को इन उपक्रमों में रोजगार कैसे मिल सकेगा ?

गत 10 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के एक भी उद्योग की स्थापना नहीं हुई है। यही कारण है कि गत 10 वर्षों में वहां कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। यदि जनता पार्टी ने तमिलनाडु तथा पांडिचेरी की इसी तरह उपेक्षा की तो फिर उसे भी वहां मुंह की खानी पड़ेगी। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि उद्योगों के मामले में भाषा सम्बन्धी समस्या उत्पन्न न हो।

तमिलनाडु में मई, जून तथा जुलाई के महीनों में बिजली में 40 से 50 प्रतिशत तक की कटौती हुई है। हमें भुगतान करने पर केरल तथा कर्नाटक से बिजली लेनी पड़ती है। अतः तमिलनाडु में छोटे पमाने के उद्योगों का विकास करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे उद्योगों में उत्पादन कम हुआ है। अतः छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

1975 में अप्रैल से अक्तूबर तक छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिए300 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जबकि 1976 में अप्रैल से अक्तूबर तक केवल 143 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यह कमी क्यों हुई है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। ऐसे आवेदकों को दीर्घ कालिक ऋण देने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे बेरोजगारी की समस्या हल करने में सहायता मिलेगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार से 50.10 करोड़ रुपए की मांग की है। किन्तु सरकार ने केवल 22.2 करोड़ रुपए दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा ग्रामोद्योगों का विकास किया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोह-अयस्क का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां लोह-अयस्क बड़ी मात्रा में है किन्तु सरकार ने लोह-अयस्क को निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस क्षेत्र से लोह-अयस्क सलेम इस्पात संयंत्र को भेजा जा सकता है। बहां से लोह-अयस्क निकालने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

उत्तरी अर्काट जिला प्रतिवर्ष 22.23 करोड़ रुपए के मूल्य का चमड़ा निर्यात करता है। लेकिन भारत सरकार ने हमारे क्षेत्र में चमड़ा कार्यालय नहीं खोला है। इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चमड़ा उत्पादक लोग अधिकांशतः गरीब लोग हैं। सरकार को इस उद्योग की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए ताकि अधिक बढ़िया किस्म का चमड़ा बनाया जा सके और अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सके।

बीड़ी पर कर लगाने से अनेकों लघु बीड़ी निर्माता एकक बन्द हो गए है या बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। यदि ऐसा हो जाएगा तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। अतः मंत्री महोदय को इस कर में कमी करनी चाहिए। यह कर सिगरेटों पर लगाया जा सकता है, जिनका उत्पादन बड़े उद्योग द्वारा किया जा सकता है।

तमिलनाडु में फिल्म उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग इस उद्योग में लगे हुए है समाज के निर्धन वर्ग के लिए मनोरंजन का एक मात्र साधन फिल्में

ही हैं। फिल्मों के उत्पादन पर लगाया गया 10 प्रतिशत शुल्क वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे इस उद्योग से सम्बन्धित लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी (शिवकाशी) : अखिल भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा किए अध्ययन प्रतिवेदन में बताया गया है कि ट्रेक्टर निर्माण उद्योगों की कुल निर्माण क्षमता 60,000 ट्रेक्टर प्रति वर्ष बनाने की है। लेकिन पिछले 6 वर्षों में यह उत्पादन 32,000 से 35,000 तक प्रति वर्ष रह गई है। अत : ट्रेक्टर और पावर टिलर उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आधुनिकी प्रौद्योगिकी किसानों तक पहुंचाई जाये। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग अर्थात मेरे चुनाव क्षेत्र के सूखाग्रस्त भागों में हजारों श्रमिकों की जीविका माचिस बनाने के काम से चल रही है। इस उद्योग में कई लोग कार्य कर रहे हैं। यह एक ऐसा उद्योग है जो समूचे वर्ष लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

खेद की बात है कि "विमको" जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसका सारा कार्य मशीनों द्वारा होता है। "विमको" माचिस के लिए मुलायम लकड़ी बहुत रियायती दरों पर खरीदता है अर्थात् 5 रुपये प्रति घन फुट। जब कि लघु एककों को यह लकड़ी खुले बाजार में 20 रुपये प्रति घन फुट की दर से खरीदनी पड़ती है। हस्त शिल्प क्षेत्र में भी कुछ एकाधिकारी पैदा हो गए हैं। इन्हें "ख" वर्ग का एकक माना जाता है। उनके उत्पादन पर कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अपने कारखाने स्थापित कर लिए हैं जिनमें परिवहन उनका अपना ही है और प्रसिद्ध व्यापार लेबल भी उन्हीं के हैं। "विमको" तथा "ख" वर्गों के एककों का बाजार में आधिपत्य है। इसके कारण "घ" वर्ग के एकक बाजार में उनके साथ स्पर्धा नहीं कर पाते। अब उनके सामने अपने कारखाने बन्द करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है।

वित्त मंत्री ने सहकारी समितियों तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के एककों को उत्पादन शुल्क में रियायत दी है। लेकिन "घ" वर्ग के एककों को यह रियायत नहीं दी गई है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में नौ सहकारी औद्योगिक सेवा समितियां हैं। किन्तु इनमें कदाचार तथा कुव्यवस्था फैली हुई है। इस मामले पर ध्यान दिया जाये।

पैरी एण्ड कम्पनी माचिस बनाने के लिए पैराफिन वैक्स तथा कच्चे सामान के एकमात्र सप्लाई करने वाली कम्पनी है। इस सामान का कुछ अभाव हो गया है और इसे बहुत महंगे भाव पर बेचा जा रहा है। सरकार को या तो इस सामान के आयात की व्यवस्था करनी चाहिए या इसका कोई विकल्प ढूंढना- चाहिए ताकि इसका अभाव न हो।

उत्पादन शुल्क में और अधिक कमी करने से "घ" वर्ग के एकको को सहायता नहीं मिलेगी, सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए ताकि सहकारी क्षेत्र में प्रशासन में सुधार हो सके। "ख" वर्ग के एककों के उत्पादन पर अधिकतम सीमा लगाई जानी चाहिए और "विमको" के लिए आंतरिक मंडी समाप्त कर दी जानी चाहिए।

छोटे एककों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल देश की माचिस की मांग पूरा कर सकते है, परन्तु निर्यात भी कर सकते हैं। वर्तमान सरकार ने यह आशा पैदा की है कि कुटीर उद्योगों को राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में बेहतर स्थान प्राप्त होगा। यदि ऐसा है तो विमको को देश के बाजार पर अधिकार करने की अनुमति क्यों दी गई है? चूंकि

[श्रीमती वी० जयलक्ष्मी]

विमको एक सुस्थापित फर्म है, इस लिए उससे कहा जाए कि वह निर्यात करे और अपना माल विदेशों में बेचे।

एक अन्य उद्योग फाऊंटेन पैन की निब बनाने का उद्योग है। देश की निबों की 70% आवश्यकता कुटीर तथा लघु एककों द्वारा पूरी की जाती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निबों का निर्माण लघु एककों द्वारा किया जा रहा है। परन्तु ये एकक भी कठिनाई में हैं। उत्तर से व्यापारी आते हैं तथा वे निबें सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और पाकिस्तान तथा बंगला देश को उन की तस्करी करते है। राज्य सरकार ने 8% की दर से कर लगा रखा है मंत्री महोदय को चाहिए कि वह राज्य सरकार को कर हटाने की सलाह दें, ताकि कुटीर उद्योगों को राहत मिल सके।

निब बनाने वाले एककों द्वारा स्टेनलैस स्टील सट्रीप्स कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस कच्चे माल का 1974 का रोलिज आदेश, 1977 में जारी किया गया है। मैं नहीं समझ सकती कि इस उद्योग को चलाने वाले कैसे अपने एककों को चला पा रहे हैं। उन्हें कच्चा माल काले बाजार से खरीदना पड़ता है। कच्चे माल की सप्लाई की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं नहीं समझ सकी कि हथकरघा उद्योग को इस मंत्रालय में शामिल क्यों नहीं किया गया हैं? जब खादी उद्योग को उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत रखा गया है, नारियल जटा उद्योग को भी इसी मंत्रालय के अन्तर्गत रखा गया है, तो हथकरघा, उद्योग को वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत क्यों रखा गया ?

मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के अतिरिक्त हथकरघा और कुटीर उद्योग ही ऐसे उद्योग हैं जिन से अधिकतम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लगभग 100 लाख व्यक्ति हथकर्घा उद्योग में लगे हुए हैं और लगभग 300 लाख व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं। यह श्रमिक बहुल ग्रामीण कुटीर उद्योग है। परन्तु यह खेद की बात है कि विद्युतचालित क्षेत्र को हथकरघा उद्योग का दर्जा दिया गया है और वह भी जनता सरकार द्वारा जिसने कि ग्रामीण हथकरघा उद्योग की सहायता करने का वचन दिया था। हथकरघा बुनकर सोचते थे कि जनता सरकार उनकी सहायता करेगी, परन्तु अब वे समझ गये हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों की हितैषी है, गरीबों की नहीं। मैं उद्योग मंत्री से अनुरोध करती हूं कि हथकरघा बुनकरों को तुरन्त राहत दी जाये। शिवरमन समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। कुछ प्रकार के कपड़ों का निर्माण केवल हथकर्घा बुनकरों के लिए ही सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए।

बीड़ी उद्योग, हाथ के औजार तथा अन्य निर्माता उद्योगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन उद्योगों पर से उत्पादन शुल्क समाप्त किया जाये ताकि छोटे उद्यमी भी पनप सकें।

दो पहियों वाला वाहन मध्यम श्रेणी के लोगों का वाहन है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस पर उत्पादन-शुल्क कम किया जाना चाहिए।

मैं अनुदानों की मांगों का विरोध करती हूं।

श्री एन्यू साहू (बोलनगीर) : मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि मांगे पेश करते हुए उन्होंने गत वर्ष की तुलना में अधिक लक्ष्य रखा है। परन्तु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 1975

में भारी उद्योगों के लिए 751 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, जब कि उत्पादन 725 करोड़ का हुआ अर्थात् लक्ष्य से 26 करोड़ कम। इस भांति वर्ष 1976-77 में 828 करोड़ का लक्ष्य रखा गया और उत्पादन 28 करोड़ कम हुआ। इस वर्ष 1020 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु मुझे सन्देह है कि यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा ?

जहां तक देश की अर्थ व्यवस्था का प्रश्न है, लगभग सभी माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि हमारी अर्थ व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। पहली तीन योजनाओं के दौरान हमें बताया गया था कि देश सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा । लेकिन पांचवीं योजना के दौरान भी हमें अनेक क्षेत्रों में अभाव का सामना करना पड़ रहा है । अतः हमें पुरानी प्रणाली को त्याग कर नये सिरे से विचार करना होगा । हमें अपनी योजना का पुनरीक्षण करना होगा । मैंने दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक प्रतिवेदन का अध्ययन किया है तथा मैंने देखा है कि जिन देशों की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है, उन की प्रति व्यक्ति आय गत तीस वर्षों में हमेशा कम रही है भारत की प्रति व्यक्ति आय 800 रुपये है, जब कि जापान की जो उद्योग पर आधारित है 27,000 रुपये। अतः हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को कृषि की बजाय उद्योग पर आधारित करना होगा। इसलिए उद्योग विभाग को महत्व-पूर्ण भूमिका निभानी होगी ।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, हमारे देश में बहुत अधिक बेरोजगारी है । वर्ष 1975-76 में बेरोजगारों की संख्या 93 लाख थी, जो 1976-77 में बढ़ कर 97 लाख हो गई और इस वर्ष के अन्त तक 1 करोड़ हो जायेगी। फिर प्रति व्यक्ति आय भी बहुत गिर गई है। अतः अब हमें अवश्य कुछ करना होगा, जिससे भूमि पर दबाव घटे तथा उद्योगों की वृद्धि हो। हमें इस समस्या पर इस संदर्भ में विचार करना होगा कि अब हमारी कृषि और अधिक व्यक्तियों को नहीं खपा सकती। अतः उद्योग पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ।

जहां तक प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को शामिल करने का सम्बन्ध है, हमें उद्योग के सभी स्तरों, आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक निर्णय लेने और उद्योग या लोकतांत्रिक निर्णय करने आदि स्तरों पर श्रमिकों को सहभागी बनाना होगा। इससे हमें उनका सहयोग मिलेगा और औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित हो जायेगी। इस का एक और विकल्प यह है कि हम अमरीकी पद्धति अपना लें। जिससे श्रमिकों और नियोजकों के बीच करार हो जाये और वे पांच वर्षों तक हड़ताल न करें। इस के अतिरिक्त एक जापानी पद्धति भी है, जिस के अनुसार वे अपना विरोध उस समय प्रकट करते हैं, जब कि उन का काम करने का समय नहीं होता। एक बार मैं टोक्यो गया, तो मैंने देखा कि श्रमिक रात को प्रदर्शन कर रहे थे। जब मैं ने पूछा कि वे रात को प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यदि हम दिन को प्रदर्शन करें तो राष्ट्र को घाटा होगा और उत्पादन में कमी आ जायेगी।

औद्योगिक विकास के संदर्भ में मैं आप का ध्यान उड़ीसा की ओर दिलाना चाहता हूं। औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 69 रुपये है जब कि अखिल भारतीय औसत 139 रुपये है। सरकार को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उड़ीसा जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिए ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, पांचवीं योजना में 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाया गया। परन्तु नारा ज्यादा लगाया गया और काम कम हुआ। फिर भी यह सच है कि देश में सरकारी

[श्री एन्थु साहू]

क्षेत्र स्थापित हो चुका है । सरकार को देखना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में ठीक कार्य हो और लाभ हो । इस के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों को पूरी छूट दी जानी चाहिए । उन्हें पूरा दायित्व सौंपा जाये । सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र में लाभ हो ।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) : माननीय मंत्री ने सरकार की औद्योगिक नीति का बड़ा विशुद्ध विवेचन किया है । इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं परन्तु सभा की यह परम्परा रही है कि सदन में जब औद्योगिक नीति जैसे महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिये जाते हैं, तो उन की प्रतियां पहले ही सदस्यों में परिचालित की जाती हैं । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में वक्तव्यों की प्रतियां पहले ही सदस्यों को दी जायें ।

मैं यह बात नहीं समझ पाया कि उद्योग और कृषि के बीच तथा भारी उद्योग और छोटे उद्योग के बीच एवं भारी उद्योग और कुटीर उद्योग के बीच तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच कोई किसी प्रकार का विवाद है । हम औद्योगिक युग में रह रहे हैं तथा औद्योगिकरण हमारी प्रगति का सूचकांक है । इस बात पर विवाद हो सकता है कि उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में से किस को अधिक महत्व दिया जाये, कितना धन आवंटित किया जाये तथा कृषि और उद्योग के बीच किस प्रकार का आवंटन अनुपात रखा जाये, परन्तु कृषि और उद्योग के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता । ये एक दूसरे के विरोधी नहीं पूरक हैं । उदाहरण के लिए अधिक कृषि उत्पादन के लिए उर्वरक और कीटनाशी दवाइयों की जरूरत होती है और उर्वरक और कीटनाशी दवाइयों के लिए बड़े-बड़े कारखाने चाहिएं । अतः इन में कोई विवाद नहीं है, अपितु एक के लिए दूसरे का विकास जरूरी है अर्थात् कृषि के विकास के लिए उद्योगों का विकास और उद्योगों के विकास के लिए कृषि का विकास जरूरी है ।

मंत्री महोदय गत तीस वर्षों के बारे में चाहे जो कहें परन्तु इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि गत तीस वर्षों में भारत में औद्योगिक आधारभूत ढांचा तैयार हो गया है । भारत आज विश्व के दस औद्योगिक राष्ट्रों में से एक है । यह संभव है कि औद्योगीकरण से सब वर्गों तथा क्षेत्रों को बराबर लाभ प्राप्त न हुआ हो, परन्तु यह कहना कि भारत में उद्योग के क्षेत्र में गत तीस वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं, सही नहीं हैं । इस संदर्भ में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उद्योगों की महानगरों में संकेन्द्रित होने की प्रवृत्ति है । औद्योगिक विकास की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संतुलित प्रगति की दृष्टि से भी इसे समाप्त किया जाना चाहिए । जब देश भर में उद्योगों का फैलाव नहीं होगा, संतुलित प्रगति सम्भव नहीं है । लाइसेंस देते समय हमें यह शर्त लगानी चाहिए कि उद्योग 5000 या 10,000 की जनसंख्या वाले ताल्लुकों, जिला मुख्यालयों या नगरों में ही आरम्भ करने होंगे । उद्योगों को बम्बई, मद्रास, दिल्ली तथा कलकत्ता जैसे महानगरों में ही केन्द्रित क्यों किया जाये ।

उद्योगों के फैलाव से मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि हम बड़े नगरों के निकट छोटे नगर बसायें । छोटे नगर बड़े नगरों की ओर बढ़ेंगे और वे बड़े नगरों में शामिल हो जायेंगे । इस से बड़े नगरों का ही क्षेत्रफल बढ़ेगा । देश में 500 जिले और 5000 तालुक है । प्रत्येक के मुख्यालय को औद्योगिक केन्द्र बनाया जाना चाहिए ।

कच्चा माल सुगमता से उपलब्ध होने के कारण हमें उन के निकट ही उद्योग स्थापित करने चाहिएं । कुछ उद्योग तो अनिवार्यतया तटीय क्षेत्रों में होते हैं, क्यों आयात और निर्यात के लिए यह आवश्यक है । परन्तु देश का संतुलित विकास तभी हो सकता है, तब देश भर में उद्योगों का फैलाव हो ।

उद्योग मंत्रालय का कई अन्य मंत्रालयों जैसा कि श्रम, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा आदि से सीधा सम्बन्ध है । विद्युत के बिना औद्योगिक और कृषिक उन्नति नहीं हो सकती । हमें देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादन करने की क्षमता बनानी चाहिए ।

Shri Chandradeo Prasad Verma (Arrah) : The hon. Minister deserves my congratulations for the assurance he has given to change the rotton industrial policy which was being followed during the last thirty years. The policy which was being followed upto now was not planned one. It is now hoped that under the stewardship of the present Minister industrial growth rate will go up.

We did not have a planned industrial policy. Our growth rate could not be more than 4 per cent. In the next five years our growth rate should be 10-12 per cent. Only then our country will prosper.

Condition of our public sector undertakings is not good. The private sector industries are trying to overpower them. We must give more attention to our public sector undertakings and ensure that they make progress by leaps and bounds. Only then our country will go ahead.

The hon. Minister comes from Bihar and as such he is well aware about the condition of U.P. and Bihar. The condition of sugar industry in these States is not good. Out of 32 sugar mills in Bihar 8-10 mills have been destroyed. The condition of other 8-10 mills, which have been taken over by State Government, is also bad. We should go into the reasons for bad condition of sugar industry and remove them. Then only condition of Bihar will improve so far as this industry is concerned.

Mill owners have not paid dues to cane growers. South Sugar Mills Ltd., which is located in Patna district has not paid the dues amounting to 20 lakhs of rupees for the last 12 years. There are six sugar mills in Western Champaran which owed 10-20 lakhs rupees to cane growers. The financial condition of cane growers is pitiable. If they give up cane cultivation, sugar industry will suffer. This matter should receive immediate attention of the Government.

Now I would like to draw the attention of the hon. Minister towards bidi industry. The hon. Finance Minister had levied an excise duty of Rupees two per thousand on bidies. The excise duty on bidis will hit the poor. You can levy excise duty on cigarettes and liquor, if you so like, but bidies should be exempted from excise duty.

Tractors are essential for the development of agriculture in the country. We must increase the production of tractors. But the price of tractors is very high. Steps must be taken to increase the production and reduce the price of tractors. Steps should also be taken to reduce the price of power tillers.

So far as cotton is concerned, in 1975-76 production of cotton fell down and raw cotton was imported. In such a situation when mills are clamouring for cotton, Maharashtra Government exported raw cotton. This is a very unfortunate situation.

The Textile Commissioner is responsible for having control over price, production and distribution of cloth. But he has no power to prosecute the erring mills. He has first to take the permission of the State Government for this purpose. My suggestion is that he should be given the necessary power to prosecute an erring mill without the permission of the State Government.

There is no proper control on production, distribution and pricing of cloth. Mill owners are making lot of money through corrupt practices. Steps should be taken to remedy the situation.

There is great potential for setting up factories in areas around Patna. Also there is great scope for setting up factories in Arrah, Phatuah, Barh Mukama and other places in North Bihar. Steps should be taken to set up factories there.

In South Bihar there are factories in public and private sector. Local people are not getting employment there. The Minister should see that local people get employment in factories.

Cottage industries should be set up in rural areas. That will help in providing employment to people.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : It is a matter of great satisfaction that Shri George Fernandes, who has been the spokesman of the poor and the down trodden is now in Government and he will take a balanced view of all the things.

[Shri M. Ram Gopal Reddy]

[कुमारी आभा मैती पीठासीन हुईं]

MISS ABHA MAITI *in the chair*

It is not proper to say that nothing had been done by the previous Government. It does not behave the hon. Members belonging to the majority party to condemn the previous Government lock stock and barrel. They must admit whatever good has been done by the previous Government. No body can deny the fact that the former Industry Ministry had been able to achieve an increase of 10 per cent in the industrial production. During his tenure of office sick textile mills started running properly. Cement factories also gave good account of themselves.

The declaration of the new Minister that monopoly houses will not be allowed to grow is welcome. It is very essential to keep the monopoly houses under check to develop small industries.

It is gratifying that our country is making headway in the manufacture of textile machinery. Machinery is being exported also. We should give necessary help for modernizing textile machinery.

We should encourage our units which are manufacturing jute machinery even though their cost of production might be some what higher than the cost of production of any multi national company. There is one Lagan Company of Calcutta. It is a multinational company and if manufactures jute machinery. It used to supply old machinery to jute mills. It never allowed them to become modern with the result that jute mills always lagged behind. But with the efforts of Shri Pari an ultra modern jute machinery was set up there and the previous minister deserves congratulations for it.

Andhra Pradesh is an industrially backward state. The Central Government should set up more and more industries there.

I congratulate the hon'ble Minister for taking charge of this Ministry. Our party will give him constructive cooperation.

With these words I conclude.

श्री विनोद भाई बी० सेठ (जामनगर) : नया पद मंत्री महोदय के लिए परिवर्तन भी है और चुनौती भी क्योंकि हमारा देश औद्योगिक क्रान्ति के कगार पर खड़ा है । उन्होंने हमेशा श्रमिकों के हितों के लिए सघर्ष किया है । अब उनके लिए समय आ गया है कि वह उद्योग श्रमिक वर्ग एव निर्धन उपभोक्ताओं के लिए भी काम करें जिनका शोषण हो रहा है ।

हमारे देश में औद्योगिक क्रान्ति विशेषकर महानगरों में आ रही है जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण विकास का अर्थ भाग कृषि का विकास नहीं अपितु ग्रामीण क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी है । इस उद्देश्य हेतु वित्त विधेयक में कुछ शिकायतें भी दी गई है । हम लघु उद्योगों के संबंध में बातें बहुत करते है लेकिन सरकार लघु पैमाने के उद्योगों की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रही । संसद में इस वर्ग को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया । कृषि और उद्योगों का विकास साथ-साथ होना चाहिए तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है । जब तक ग्राम एवं कुटीर उद्योगों का विकास नहीं किया जाता तब तक देश में वह औद्योगिक क्रान्ति नहीं आ सकती जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी । जनता पार्टी के घोषणा पत्र ने हमें पहली बार यह आश्वासन दिया है कि देश के इस उपेक्षित क्षेत्र की ओर अब कुछ ध्यान दिया जाएगा ।

गुजरात की स्थिति ठीक नहीं है । बाढ़ों और तुफानों से यह बुरी तरह प्रभावित हुआ है । गुजरात में शुभलक्ष्मी एवं प्रियलक्ष्मी रुग्ण मिलें है । श्रमिक वर्ग निरन्तर यह मांग करता आ रहा है कि सरकार इन मिलों को अपने हाथ में ले ले । सरकार के यह निर्णय के बाद कि ऐसी मिलों का प्रबंध ग्रहण नहीं होगा आंध्र प्रदेश की मिलों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । क्या

यह गुजरात के साथ भेद-भाव नहीं है ? मंत्री महोदय मामले की जांच करें और श्रमिकों की सहायता हेतु यह दो मिलें अपने हाथ में ले लें ।

भावनगर में मशीन टूल कारखाना बनाने का प्रस्ताव था । जितनी जल्दी यह कारखाना बनाया जाए उतना अच्छा होगा । गुजरात में बन्दरगाह आधारित सीमेंट उद्योग खोला जा सकता है क्योंकि जाफराबाद में अपेक्षित कच्चे माल का भंडार है ।

कच्छ में खनिज भंडार उपलब्ध है लेकिन सरकार ने कच्छ में एल्यूमीना उद्योग स्थापित करने में कोई रुचि नहीं ली है । कच्छ में चांदी की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं । केन्द्रीय सरकार को इस उद्योग को कुछ सहायता देनी चाहिए ।

लघु इस्पात संयंत्र देश की ऐसे समय में मदद करते है जबकि इस्पात की आवश्यकता होती है । यह बिजली पर आधारित उद्योग है । यह उद्योग अब समाप्त हो रहा है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरकारी सहायता के अभाव में ही यह उद्योग समाप्त हो रहा है ।

सूरत का आर्ट सिल्क उद्योग विश्व का सबसे उत्तम उद्योग है । सूरत नवसारी तथा भावनगर में हीरा उद्योग पनप रहा है । सरकार को इस उद्योग को नियमित करना चाहिए तथा उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस उद्योग में लगे श्रमिकों को उनका हिस्सा मिले ।

महानगरों में औद्योगिक विकास के कारण वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है । सरकार को बड़े नगरों में, सुन्दरगढ़ क्षेत्र में उद्योग न स्थापित करने का निर्णय करना चाहिए ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जामनगर में कई लघु उद्योग हैं । विशेषकर कांस्य बर्तन तथा कशीदाकारी उद्योगों को कठिनाइयां हो रही है । सरकार को इस उद्योग की समस्याओं पर विचार करना चाहिए ।

जामनगर में एक निपुण मिस्त्री ने एक मोटर का आविष्कार किया है जोकि मारूति से कहीं अच्छी है । अब इस मिस्त्री को मोटरकार बनाने का लाइसेंस दिया गया है । आशा है कि वर्तमान मंत्री के प्रोत्साहन से वह अपनी परियोजना में सफल होगा ।

अधिकांश लघु उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या उत्पाद शुल्क की अदायगी की है । शुल्क निर्धारित करने के तरीके में परिवर्तन किया जाना चाहिए । सोडे की बोतल जिस पर 10 पैसे की लागत आती है उसे भी उत्पाद शुल्क अदा करना पड़ रहा है ।

उद्योगों में औद्योगिक श्रमिकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अतः उन्हें भी प्रबंधक वर्ग की भांति मुनाफे में हिस्सा दिया जाना चाहिए । उद्योगपतियों को इस संबंध में अपना रवैया बदलना चाहिए । उन्हें केवल अपने परिवार का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए अपितु सारे राष्ट्र के हितों को दृष्टिगत रखना चाहिए । हमें अपने उद्योगपतियों को बताना चाहिए कि हमारे सभी नए उद्योग रोजगारोन्मुख होने चाहिएं ताकि उपभोक्ता वस्तु उद्योग देश की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।

केन्द्र सरकार ने पिछड़े राज्यों एवं जिलों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है । उद्योगों के विकास में भी क्षेत्रीय असमानताएं हैं । सरकार एवं उद्योगपतियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए । ऐसे कई उद्योग क्षेत्र हैं जहां कई रुग्ण उद्योग हैं । हमें नए उद्योग स्थापित करने से पूर्व रुग्ण उद्योगों को फिर से चालू करना चाहिए ।

[श्री विनोद भाई बी० सेठ]

नमक आयुक्त का कार्यालय जामनगर में होना चाहिए। देश का 40 प्रतिशत नमक यहां पैदा होता है अभी तक यह कार्यालय जयपुर में क्यों है। यह कार्यालय जामनगर में ही होना चाहिए क्योंकि यहां नमक बनता है।

गुजरात में उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। मोरवी में घड़ी उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ गया है। उद्योग की सहयता हेतु कार्यवाही की जाए। मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रहित में समस्याओं के समाधान हेतु सचिवों और मंत्रियों की हर तीन महीने बाद बैठकें होनी चाहिए।

Shri Subhash Ahuja (Betul) : Industrial development has brought prosperity to the country. But our industrial development has not been even. Certain backward areas have been completely ignored. There is need for dispersal of industries. There should be a net work of industries in backward areas.

Since 1968 more than a lakh of our youngmen has been given industrial training. But majority of the trained youngmen are without employment. Steps should be taken to provide jobs to these people.

Madhya Pradesh is industrially backward. Out of 45 districts 32 districts are backward although minerals like bauxite, iron ore and coal, etc. are available there in large quantity yet there is widespread unemployment. There only few cities like Indore, Ujjain, Ratlam, Jabalpur, Bhopal, Gwalior and Raipur etc are flourishing. My district Betul as also a very backward district. No industrial unit has been set up in this district during 30 years of independence. There is widespread unemployment there. Betul district should be declared a backward district and steps should be taken for its industrial development.

श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग) : सबसे पहले मैं नए मंत्री महोदय को कार्यभार संभालने पर बधाई देता हूं। लोगों को यह आशंका थी कि जनता पार्टी के सत्ता में आने से औद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तन होगा। क्योंकि जनता पार्टी के औद्योगिक नीति के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार हैं। कुछ सदस्य सरकारी क्षेत्र के पक्ष में नहीं है और वह इस क्षेत्र को निरुत्साहित करना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री का विचार है कि सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को ही समान रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हमारे गृह मंत्री कृषि के अधिक पक्ष में हैं। हमारे भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री बृजलाल वर्मा ने कहा है कि सरकार की नीति भूतपूर्व सरकार की भांति उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग को प्रोत्साहन देने की नहीं। सरकारी क्षेत्र में आधारभूत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और गैर-सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार इन नेताओं ने अपने वक्तव्य दिए उससे लोगों को यह शक था कि जनता सरकार कांग्रेस सरकार की नीतियों को बदल देगी लेकिन मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों को नहीं बदला है।

सरकारी क्षेत्रों के जो उद्योग, खाद्य, उर्वरक, तेल और अन्य ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जिन की आम जनता को आवश्यकता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

जहां तक लघु पैमाने के उद्योगों का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, ग्राम उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। बड़े उद्योगों को उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिनका उत्पादन लघु उद्योगों अथवा कुटीर उद्योगों के माध्यम से हो सकता है।

लघु उद्योगों में अधिक पूंजी निवेश नहीं करनी पड़ती। यह उद्योग श्रम प्रधान होते है। अतः इन उद्यागों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। सरकार को विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। लघु पैमाने के उद्योगों अर्थात् कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के विपणन की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इन उद्योगों के उत्पादों के लिए सरकार को विपणन व्यवस्था करनी चाहिए।

बड़े-बड़े उद्योगपति बड़े-बड़े महानगरों में उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं। उन नगरों में आगे ही काफी उद्योग है। इन लोगों को कहा जाना चाहिए कि वे उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करे।

गरीबी, बेकारी, आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

योजना आयोग ने 240 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ करार किया है। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए कई रियायतें दी गई हैं। मैं चाहता हूं इन रियातों में विपणन सुविधाओं को भी शामिल कर लिया जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र चिखली को भी योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्र रूप में घोषित किया है। इस क्षेत्र में सीमेन्ट फैक्टरी स्थापित करने के लिये कच्चा माल उपलब्ध है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस क्षेत्र में एक सीमेंट का कारखाना बनाए यहां लौह अयस्क और मैंगनीज के भंडार भी बहुत है लेकिन खनन उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। खनन उद्योग भी चालू होना चाहिए। अन्त में मैं मंत्री महोदय को उद्योगों के संबंध में गतिशील और समाजवादी नीति लाने के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद।

Shri Laxman Rao Mankar (Bhandara) : In the past we had spent most of the money on big industries. A huge amount is invested in these industries. We should see how much net profit these enterprises have earned. Last year they had profit of only 2 crores. In the year 1968-69 they suffered a loss of 28 crores. Government is not getting its due return. Unemployment has been increasing plan to plan whereas the number of unemployed at the end of 1st five year plan was 1 crore today the figures have gone up to 4·20 crores now. If we want to solve this problem we will have to pay more attention to small industries. Unfortunately so far we have been investing very little money in small industries. It is time Government thinks of investing more money in small industry as they can provide employment to a larger number of people than the big industries.

The Government should seriously think of investing maximum funds on the small scale industries so that a number of unemployed persons could be adjusted in these industries. The industrial policy of the country should be labour-oriented.

Industries are centralized in the big cities. We should decentralise the industries which should be set up in the villages and small cities. so that villagers could get employment. Large scale industries should be set up in the public sector only but the investment should not be dead one.

The overall policy regarding declaration of industrially backward Distts. should be reviewed. In addition, implementation, machinery at all levelled should be tighte. ed. There should be separate cell for the same.

There should be a good implementation machinery in the rural areas.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : उद्योग मंत्री ने एक संतोषजनक औद्योगिक नीति की घोषणा की है लेकिन वित्त मंत्री का बजट इस घोषित नीति के विरुद्ध है।

मंत्री ने कहा है कि प्रसाधन वस्तुओं, बिस्कुट आदि के लिये हमें तकनीकी जानकारी तथा विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हमें बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों के औद्योगिक कार्यकलापों की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इन गृहों ने अपने हितों की पूर्ति के लिये देश की अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार अस्त-व्यस्त की।

[श्री के० लकप्पा]

मंत्री महोदय ने माल का उत्पादन और वितरण बढ़ाने, आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा रोज़गार के अवसर पैदा करने के सम्बन्ध में एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है। उसके लिये हमें इस बजट से अधिक आशा नहीं रखनी चाहिए।

कहा गया है कि 10 साल के अन्दर 5 करोड़ लोगों को रोज़गार उपलब्ध किया जायेगा। अधिक रोज़गार खोलने के लिये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना अनिवार्य है लेकिन इस हेतु जो कार्यक्रम बनाया गया है वह संतोषजनक नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किये बिना हम 10 साल के अन्दर 5 करोड़ लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं कर सकते।

सीमेंट के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र की वितरण व्यवस्था पूर्णतः असफल रही है। जनता सरकार बनने के बाद मूल्य बढ़ गये हैं। सरकार वितरण प्रणाली को नियंत्रित कर सकती थी। सीमेंट कारखाने कम्पनी कानून का उपयोग करते हुए बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। मंत्री इन बातों पर रोक क्यों नहीं लगा सकते? सीमेंट, तेल तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के वितरण को सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती थी। ऐसा करने पर ही मूल्य नियंत्रित हो सकते हैं।

देश में ट्रेक्टरों का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है और कारखाने के मालिक घटिया किस्म के ट्रेक्टर तैयार करके बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। इसके लिये नई तकनीकी जानकारी विकसित करना जरूरी है। ट्रेक्टरों के दाम कम करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।

स्टेनलैस स्टील पर लगे आयात शुल्क से छोटे कारखानों के मालिक हानि में रहेंगे। उद्योग मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

Shri Nathu Singh (Dausa): India is predominently agriculturist country. Countrymen were exploited by the industrialists during the last 30 years.

The growth rate of assets of monopoly houses in the country was 15 per cent per annum whereas the national income was only 3·5 per cent. During the last 20 years, the industrial growth was only 7 per cent but the unemployment increased by 11·1 per cent. The Minister should devise measures to link industrial production with the employment potential and to tackle the problem of unemployment. There are about 50 millions of unemployed people in the country today because the technology that we have adopted is not in consonance with Indian conditions. We did not pay adequate attention to small scale industries. During the last 5 years only an amount of Rs. 330·60 crores was spent whereas on big industries, Rs. 8964 crores of rupees were spent.

The workers have been exploited so far. Government should take steps to see that they are not only associated with the administration, but made partners in the industry.

It is said that big foreign companies were given licences to produce consumer goods and there are no arrangements to produce them on the small scale sector. These consumers goods should be produced by small scale industry.

Public sector industries are still running in loss because this sector is being given too much of freedom.

Big industries have mostly been opened in urban areas. Even small scale industries are being opened in the cities. Rajasthan is very rich in natural resources and minerals. The entire state should be declared as a backward state and steps should be taken to start small industries in rural areas.

The raw material should be used in the country itself and the export of engineering goods should be increased. Cheap tractors should be manufactured. A National Fund should be set up to assist small industries.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : देश के सामने मुद्रास्फीति तथा बेरोज़गारी की समस्या है। इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये लगाये गये जिसमें से सरकार 100 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकती है। बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने से बेरोज़गारी दूर नहीं हो सकती। ग्रामीण विकास की ओर जनता सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

आय बढ़ाने तथा मजदूरी बढ़ाने मात्र से ही लाभ नहीं होगा। योग्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये ताकि उन्हें रोज़गार उपलब्ध किया जा सके। आज की स्थिति में, छोटे उद्योगों का ढांचा बदल गया है। विदेशों से ऐसे माल की मांग बढ़ती जा रही है। जिनका उत्पादन छोटे उद्योगों में ही हो सकता है। हम निर्यात के लिये ऐनक के फ्रेम भी बना सकते हैं।

उद्योगों के संकटग्रस्त रहने का कारण कारखाने का आधुनिकीकरण है। 1961 तथा 1971 के बीच श्रम लागत 220 प्रतिशत तथा कच्चे माल की लागत 181 प्रतिशत बढ़ गयी है। प्रति-स्थापन लागत 10 वर्षों में दुगनी हो गई है। अत: जितनी भी मूल्य ह्रास आरक्षित निधि जमा की गई थी वह मशीनरी तथा उपकरणों को बदलने के लिये पर्याप्त नहीं पाई गई। इसलिये घटिया या पुरानी मशीनरी तथा उपकरणों से काम चलाना पड़ा। गत 20 वर्षों के औद्योगिक कार्यसंचालनों की आकस्मिकताओं के अनुरूप कराधान नीति का समायोजन करना होगा।

ऋण नीति में कुछ ग्रामीण आधार होना चाहिए। मेरे विचार में हमें अपनी नई आवश्यकताओं के अनुरूप हमें ऋण नीति में परिवर्तन करना होगा। ऋण नीति रिज़र्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय स्तर पर बनाई जाती है। वे इसकी समीक्षा कर सकते हैं। वर्तमान ऋण नीति में कुछ कमियां, कुछ दोष हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

हमारी निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताएं भी अनेक प्रकार की हैं। निर्यात प्रधान विकास के लिये विदेशी मुद्रा कोष को बनाये रखने तथा ऋणों की बकाया राशि की अदायगी तभी की जा सकती है जब हम अधिकाधिक निर्यात करें।

श्री बशीर अहमद (फतेहपुर) : भूतपूर्व सरकार ने एक ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जिसका क्रियान्वयन न तो किया जा सकता था और न ही उसका क्रियान्वयन हुआ। भूतपूर्व सरकार ने किसी सुदृढ़ औद्योगिक नीति के आधार पर नहीं अपितु राजनीतिक आधार पर बिना उचित योजना के औद्योगिक एककों की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के राय बरेली क्षेत्र में, जो कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री का निर्वाचन-क्षेत्र है, अनेक औद्योगिक एककों की स्थापना की गई।

भूतपूर्व सरकार के शासन में कई चीनी की मिलें रुग्ण हो गई थीं। जहां तक कपड़ा मिलों का सम्बन्ध है, बड़े शहरों तथा नगरों में बहुत अधिक मिलें स्थापित किये जाने के कारण ये मिलें रुग्ण हो गई हैं।

हमें एक नई औद्योगिक नीति बनानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बड़े उद्योग उन क्षेत्रों में स्थापित करने चाहियें जो वास्तव में पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। इस सम्बन्ध में बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

पिछली नीति के परिणामस्वरूप एकाधिकार गृहों की संख्या में वृद्धि हुई है और सम्पत्ति कुछेक लोगों के हाथों में आ गई है। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि सारी सम्पत्ति इन चन्द

[श्री बशीर अहमद]

लोगों के हाथों में कैसे आ गई ? एकाधिकार गृहों के सम्बन्ध में नीति को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए । एकाधिकार गृहों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए ।

भारत को विभिन्न औद्योगिक ज़ोनों में बांट देना चाहिए और ये ज़ोन विभिन्न आयोगों और समितियों, जिनमें सरकारी तथा गैर-सरकारी संसद सदस्य, तकनीशियन इत्यादि लोग हों, के प्रचार के अन्तर्गत रखे जाने चाहियें । उन्हें विभिन्न भागों का सर्वेक्षण करना चाहिए तथा एक विशिष्ट क्षेत्र के औद्योगिकीकरण के सम्बन्ध में मौके पर ही निर्णय लेना चाहिए ।

बीड़ी उद्योग भी कुटीर उद्योग है । इस उद्योग पर अधिक उत्पाद शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं और निर्धन मजदूरों को ही नुकसान हुआ है । वित्त मंत्री को लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को समाप्त करने के लिये उद्योग मंत्री वित्त मंत्री से अनुरोध करें ।

हथकरघा उद्योग को भी उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाना चाहिए । सरकार ने हथकरघा उद्योग को जो संरक्षण दे रखा था वह हथकरघे के कपड़ों पर उत्पाद शुल्क लगा कर एक प्रकार से समाप्त हो गया है । इसके परिणामस्वरूप कपड़ा उद्योग को हथकरघा उद्योग की तुलना में प्राथमिकता दी गई है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था । हथकरघा उद्योग पर उत्पाद शुल्क के लगाये जाने से लगभग $2\frac{1}{2}$ करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं । बजट में हथकरघा उद्योग को विद्युत करघा उद्योग के बराबर रखा गया है । हथकरघा उद्योग पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने से बड़े-बड़े कपड़ा उद्योग विद्युत करघों से कपड़ा बुनवाकर कपड़ा उद्योग से उसका परिष्करण करवायेंगे । यह नीति के बिल्कुल विपरीत है । उद्योग मंत्री हस्तक्षेप करके बजट में अपेक्षित संशोधन करवायें ।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Manohar Lal (Kanpur) : The Congress Government has ruined our economy. Its policies have been responsible for creating widespread unemployment. This has led to frustration among our young people. The Congress Government had completely forgotten the ideals of Mahatma Gandhi.

Our country can progress by setting up small scale industries. There should be more and more agro-industries. The previous government had neglected production of consumer goods required by the Common people. They gave licences for setting up industries to big industrialists. Also import licences were given to these people.

The Congress Government had given licences for import of edible oils this year. The industrialists, who were given these licences, misused them and sold edible oil in black market in foreign countries. No licence should be given to these industrialists in future. Only goods produced by small and cottage industries should be sold for internal consumption. We should give all encouragement to small scale industries. Only then our country will be able to march ahead.

Sick textile mills are run by N.T.C. Managing Directors appointed by Government are looking after these mills. The I.A.S. and I.C.S. Officers have no experience of running these mills.

There is a government undertaking TEFCO in Kanpur. It is suffering a loss of Rs. 10 lakhs per month. This undertaking is over-staffed and appointments are made on the basis of nepotism. The hon. Minister should look into the affairs of this undertaking.

Kailash Mill is lying closed for the last one year. More than five thousand workers are jobless. The Minister should attend to this mill also.

An excise duty has been imposed on leather goods. This will hit hard small scale industries engaged in the production of leather goods in Kanpur and Agra. The Government should look into this matter.

There has been income-tax evasion so far. But now people are not paying excise duty. The Government should take steps to check this evation.

We have to increase our production both agricultural and industrial. Then alone it will be possible to check price rise. Also implements required by farmers should be manufactured by small scale industries.

The Government should urge upon industries both in the public and private sectors to reserve ten percent of jobs for educated unemployed. This will help the educated youngmen, who are without jobs.

With these words I support the Demands for Grants in respect of Ministry of Industries.

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (अदीलाबाद) : मंत्री महोदय ने कल सुबह जनता पार्टी की नीति स्पष्ट की। इसके लिये में उन्हें बधाई देता हूं। मंत्री महोदय द्वारा दिया गया नीति वक्तव्य तथा उनके द्वारा पेश की गई मांग परस्पर विरोधी हैं।

मंत्री महोदय ने अपने नीति वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि वह कुटीर उद्योग को एवं लघु उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। लेकिन बजट में अन्य उद्योगों के लिये 265 करोड़ रुपये और कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिये रुपये 82.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा कि उद्योगों को श्रम-प्रधान बनाया जायेगा। लघु उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक श्रम प्रधान होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें।

सरकारी क्षेत्र की सफलता के लिये तीन समस्याएं हल करनी होंगी। किसी भी औद्योगिक नीति की सफलता के लिये मंत्री महोदय को सही तरीके से नौकरशाही को समाप्त करना होगा। तब उनको श्रमिक समस्याएं हल करनी होंगी। हमारे पास बिजली की कमी है। समस्या के इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

गत वर्ष के बजट में भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत पांच स्थानों का चयन 5 सीमेंट कारखाने लगाने के लिये किया गया था। लेकिन केवल 3 सीमेंट कारखानों की अनुमति दी गई। आन्ध्र प्रदेश तथा आदिलाबाद में एक-एक कारखाना लगाने की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है। इन दो कारखानों के लिये यथाशीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहियें।

बजट में स्पष्ट कहा गया है कि कुछ घड़ियों का आयात किया जायेगा। घड़ियों की मांग की अपेक्षा हमारा उत्पादन कहीं कम है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि हम अन्य देशों से इसका आयात करें। ऐसा करना मंत्री महोदय द्वारा घोषित उद्योग नीति के विरुद्ध होगा।

बिरला बन्धुओं तथा अन्य लोगों द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधिश न्यायमूर्ति ए० के० सरकार की अध्यक्षता में 18-2-1970 को एक जांच आयोग गठित किया गया। 8 वर्ष हो गये है और काम इसलिये रुक गया है क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रोकादेश दिया हुआ है। दो वर्ष बाद इसको दस वर्ष हो जायेंगे और तब तक इस की जांच में लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च हो चूके होंगे जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जांचों पर ऐसे अनावश्यक व्यय की व्यवस्था बजट में नहीं होनी चाहिये।

[श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी]

जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है कठिनाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तब तक उद्योग शुरु नहीं किये जा सकते जब तक वहां बिजली, पानी, कच्चा माल तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध न हों। अत: क्रियान्वयन इतना आसान नहीं है।

बीड़ी उद्योग एक कुटीर उद्योग है। इस पर दुगना उत्पाद शुल्क लगता है। बीड़ी की लागत में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बीडी अधिकतर किसान या मजदूर पीते हैं। बीडी उद्योग श्रम-प्रधान उद्योग है। अत: यह काय भी कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के खिलाफ जाता है।

बड़े उद्योगों में इस वर्ष प्रबन्ध व्यवस्था बिल्कूल समाप्त हो गई है। श्रमिक समस्या भी पैदा हुई है। यदि हम न्यूनतम 10 प्रतिशत विकास की दर का लक्ष्य पूरा करना है तो मंत्री महोदय को नौकरशाही से सावधान रहना होगा।

Shri Durga Chand (Kangra) : Government have stated that they will pay more attention to backward areas in the country and will set up industries with a view t removing their backwardness. Himachal Pradesh is one of the backward states of our country. It is rich in natural resources but so far these resources have not been fully exploited and those partially exploited did not benefit the people there. There are no industries there. Even a small item of furniture has to be p rchased from outside the state. I will, therefore, urge upon the Minister to look into it and take effective steps to accelerate industrial development of Himachal Pradesh.

During the fifth plan the total outlay on industry and mines in the Central Sector has been to the tune of Rs. 10,200 crores. But only a small part of it has been earmarked for the small scale industries although it is the professed policy of Janata Party to invest more for the development of these industries. This investment should be increased in the next budget.

There has not been a proper survey of mineral resources in Himachal Pradesh by the Geological Survey of India. There are rich deposits of mica, iron, coal and lime stone which can be exploited fully. So I shall request the hon. Minister to expedite the exploitation of mineral resources. Cement can be manufactured at a very large scale in that State.

Government must also explore possibilities of establishing cement factory in Himachal Pradesh. Similarly factories for making drugs and chemicals can be installed there. There is scope for esta lishing manufacturing units of matches, resin, fertilisers etc.

The employment opportunities in Himachal Pradesh are very few. That is why people come to big cities and do petty jobs here. The Congress Government failed to develop both agriculture and industry in this region during the last 30 years. But it is really regrettable that a paltry sum of less than one crore has been earmarked for Himachal Pradesh. More funds should be allocated for this purpose.

You are investing crores of rupees in other parts of the country but Himachal Pradesh which is rich in minerals receives the minimum attention. This state is backward area. So we must take urgent steps for its developm nt.

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : सभापति महोदय पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर पांचवी योजना तक बेरोजगारी में वृद्धि ही हुई है और आज 4 करोड़ आदमी बेरोजगार हैं।

सदैव ही सिविल कर्मचारियों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों का प्रभारी अधिकारी बना दिया जाता है। उद्योगों को चलाने के लिए ऐसे अधिकारी स्वयं उन्हीं उद्योगों में से लिए जाने चाहियें जो रोजगार प्रधान नीति का अनुसरण करें। वे यह भी ध्यान रखेंगे कि उद्योग घाटे में न जाकर लाभ अर्जित करें।

ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिये। सभी पूर्वोत्तर राज्यों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र घोषित किये जाने चाहियें तथा नये उद्यमकर्ताओं की सहायता से अधिक पूंजी निवेश किया जाये।

बन्द पड़े चाय बागान का प्रबन्ध ग्रहण सरकार द्वारा या भारतीय चाय निगम द्वारा श्रमिकों के रोजगार को बनाये रखने के तर्क पर किया जाता है। मेरा सुझाव है कि ऐसे चाय बागान श्रमिकों अथवा सहकारी समितियों को सौंप दिये जायें। सरकार को धन तथा तकनीकी जानकारी द्वारा उनकी सहायता करनी चाहिये। उद्योग विभाग को चाहिये कि बिजली विभाग के साथ मिल कर पूर्वोत्तर भारत को छोटी पहाड़ी नदियों पर लघु पन-बिजली परियोजनाएं शुरु करे। इस से इस क्षेत्र के बड़े तथा छोटे औद्योगिक एककों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा की जा सकेगी।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन सम्पदा भरपूर है। यहां जंगल ही जंगल है। अरब देशों में 'अगार' 4000 रु० प्रति किलो बेची जाती है। असम में यही चीज काफी मात्रा में उपलब्ध है। 'अगार' उद्योग छोटे तथा बड़े पैमाने पर राज्य में ही शुरु किया जा सकता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने बड़ी भारतीय फर्मों के साथ सांठ-गांठ करके चाय-बागान खरीद लिए हैं। पर ये कम्पनियां ऐसी नीति अपनाती हैं जिन से कम से कम श्रमिकों को रोजगार मिले। इसीलिए 15-20 वर्षों की अपेक्षा आज इस क्षेत्र में बरोजगारी अधिक है। मंत्री जी इस समस्या पर विचार करें और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को चाय बागान खरीदने की अनुमति न दी जाये।

कई बार ऐसा भी देखा गया है कि देश में तकनीकी जानकारी उपलब्ध होने पर भी उसे विदेशों से आयात किया जाता है। उदाहरण के लिए बोंबगाईगांव पैट्रो रसायन उद्योग में लगे इंजीनियर पश्चिम जर्मनी ब्रिटैन और फ्रांस का चक्कर लगाते रहते हैं। इस कारण बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अपव्यय होता है। हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री दिनेश चन्द्र जोरदर (माल्दा) : यह हर्ष की बात है कि नये वित्त मंत्री ने नई औद्योगिक नीति में नये विचार रखे हैं। आशा है कि कुछ क्रान्तिकारी परिवतन होंगे। अब तक की नीतियों से जहां औद्योगिक प्रगति हुई है वहां बरोजगारी बढ़ी है और अनिवार्य वस्तुओं के विवरण में विषमता बढ़ी है।

अपने उद्योगों के विकास के लिए हमें लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाना होगा। उसके लिए भूमि सुधार कानूनों तथा राष्ट्रीय मजूरी नीति जैसे कानूनों को कार्यान्वित करना होगा अन्यथा तीव्र गति से औद्योगिक विकास सम्भव नहीं।

उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता वस्तुओं आवश्यक दवाओं स्टेण्डर्ड कपड़े तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य निर्धारित कर देने चाहिये। ऐसा किये वगेर क्रय शक्ति भी नहीं बढ़ सकती।

पिछली सरकार के शासन के दौरान बहुत से उद्योग रुग्न हो गये हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने करोड़ों रुपये के लाभ को सही उद्योग में लगाने की बजाये अतिरिक्त धन को अन्य उद्योगों में लगा दिया। हमें उद्योगों को रुग्ण होने से बचाने के प्रयास करने चाहिये।

अब बहुराष्ट्रीय निगम देश के उद्योगों में प्रवेश कर गये हैं। उदाहरण के लिए सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात छोटे परिवारों ने शुरु किया था जिनके रिशतेदार विदेशों में हैं। पर अब नहीं काम 10-12 बड़ी फर्में कर रही है और छोटे एककों को निगल रही हैं। यूनियन कार्बाइड हैं समुद्री उत्पाद तथा खाद्य संयरण उद्योग का काम शुरु कर दिया है। ब्रिटानिया कम्पनी ने भी ऐसे छोटे उद्योग शुरु कर दिये हैं। इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

[श्री दिनेश चन्द्र जोरदर]

कई संस्थापित कम्पननियां रुग्ण होकर बन्द हो चुकी हैं। जैसे नेशनल आयरन एण्ड स्टील कार्पोरेशन दि नेशनल रबड़ कम्पनी तथा नेहाटी वर्ट की एण्ड स्टाक कम्पनी 4–5 वर्षों से बन्द पड़ी हैं। उन्हें पुनः चालू करने के लिए कुछ नहीं किया गया। इसी प्रकार नेहाटी का इंडिन पेपर प्लाट एवरेस्ट साईकिल कम्पनी सेन रेलें कम्पनी आदि भी कुछ समय से बन्द पड़ी हैं।

हम साईकलों का निर्यात करते हैं और उनकी घरेलू मांग भी है। फिर सेन टेले कम्पनी क्यों बंद पड़ी है ?

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : हाल ही में घोषित औद्योगिक नीति से जनता पार्टी में आंतरिक मतभेदों का पता चलता है। हर आदमी अलग दिशा में जा रहा है। जनता पार्टी के आगमन से उद्योगपति समझने लगे हैं कि उन्हें श्रमिकों के शोषण का अधिकार मिल गया है। वे शोषण करते हैं तालाबन्दी कर रहे हैं तथा श्रमिकों की छंटनी कर रहे हैं। उनकी श्रमिक विरोधी नीति को समाप्त करने पर मंत्री जी को विचार करना चाहिये।

यह ठीक है कि जनता सरकार ग्रामोद्योग का विकास करना चाहती है। पर जब तक बिजली विकास एवं ग्रामों में कार्यकुशलता का विकास करके आधारभूत ढांचा नहीं बना लिया जाता तब तक हम उद्योगों का विकास कसे कर सकते हैं। यदि हम वास्तव में उद्योग समूह स्थापित करना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक वातावरण पैदा करना चाहते हैं तो हमारे पास समेकित योजना होनी चाहिये। हमें जापान का अनुकरण करना चाहिये। हम केरल का उदाहरण ले सकते हैं। वहां भी छोटे उद्योग स्थापित करके लघु क्षेत्र बनाये गये हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तूर में बहुत आम होते हैं। उद्योग मंत्रालय को वहां फल संरक्षण उद्योग की स्थापना करनी चाहिये तथा रेनीगुंट में तिरुपति के निकट औद्योगिक समूह स्थापित किया जा सकता है।

सभापति महोदय : मंत्री जी सोमवार को प्रश्न काल के बाद उत्तर देंगे। अब सभा स्थगित होती है और सोमवार को 11 बजे पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 जुलाई, 1977/20 अषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 11, 1977/Asadha 20, 1899 (Saka)

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०–एल० एस० III—1998 एल० एस०–7-10-77—200